(ग) सरकार इन एककों को पुर्नजीवित करने के लिये क्या प्रयास कर रही है ;

(घ) इन एककों के बन्द होने के परिणामस्वरूप रोजगार से वंचित होने वाले कर्मचारियों और कामगारों की संख्या कितनी है ; और

(ङ) क्या इन एककों के कामगारों को राष्ट्रीय राजस्व निधि से कोई राहत प्रदान की जाती है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

देश में मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों के नाम

1945. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में मान्यता प्राप्त श्रमिकों संघों के नाम क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1992-93 में ऐसे प्रत्येक श्रमिक संघ की कुल सदस्यता संख्या कितनी थी ; और

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल सदस्यता संख्या कम होने की वजह से किसी श्रमिक संघ की मान्यता रद्द की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) 31-12-1980 की गणना की तारीख मानकर आयोजित पिछले सामान्य सत्यापन के आधार पर विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, समितियों, परिषदों, वेतन बोर्डों आदि में निम्नलिखित केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है । 31-12-1980 की स्थिति के अनुसार उनकी सत्यापित सदस्यता उनके नामों के सामने दी गयी है :—

क्रम सं०	केन्द्रीय संगठन का नाम	31-12-1980 की स्थिति के अनुसार सत्यापित सदस्यता
1.	आई एन टी यू सी	22,36,128
2.	बी एम एस	12,11,345
3.	एच एम एस	6,62,882
4.	यू टी यू सी (एल एस)	6,21,359
5.	एन एल ओ	2,46,540
6.	यू टी यू सी	1,65,614
7.	टी यू सी सी	1,23,048
8.	एन एफ आई टी यू	84,123
9.	ए आई टी यू सी	3,44,746
10.	सी आई टी यू	3,31,031
	कुल :	61,26,816

31-12-1989 को गणना की तारीख मानकर केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों की सदस्यता का निर्धारण करने के लिये सामान्य सत्यापन कार्य शुरू किया जा चुका है और सत्यापन का कार्य प्रगति पर है ।

चूंकि किसी केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठन को मान्यता प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है अतः मान्यता को रद्द किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

Generation of Employment

1946. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE : Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state :

(a) the thrust/strategy adopted during the Eighth Five Year Plan for the generation of employment ; and